>

Title: Regarding need to provide adequate storage facilities for food grains and issue of sufficient quantities of jute bags for packing in the country.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आज देश के सामने किसानों से संबंधित एक गंभीर सवाल है। सरकार की कोशिश रही कि देश में किसी भी तरह से अन्न की पैदावार बढ़े। पंजाब से लेकर पूरे देश के किसानों ने अन्न की पैदावार बढ़ाई है लेकिन अन्न की पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में पहले बहुत कम पैदावार होती थी लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अन्न की पैदावार उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन क्या ज्यादा पैदावार करने की सजा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगी? हर साल किसानों के साथ यही हो रहा है और हर साल यहां हम यह सवाल उठाते हैं। आज किसान ज्यादा अन्न पैदा करके बेचना चाहता है, कांटे भी प्रदेशों में लगे हुए हैं, सरकार खरीदारी भी कर रही है लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि अन्न के लिए बोरा नहीं है, किसान गेहूं किसमें भरे? आज न अन्न के लिए पर्याप्त गोदाम हैं न ही पर्याप्त बोरे हैं। ऐसी स्थिति मैं 10-12 साल से देख रहा हूं। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी और नेता सदन से व्यक्तिगत रूप से मैंने बात की और उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की समस्या है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस समस्या का समाधान अगर आप अभी से करेंगे तो शायद यह समस्या अगले साल न आये। गोदामों का बनाना और बोरे की समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज किसान को इतनी बड़ी सजा मिल रही है, वह अपने अन्न को कहां ले जाए, बारिश आने वाली है और कहीं-कहीं बारिश शुरू भी हो गयी है। नतीजा यह होगा कि गेहूं सड़ेगा। एक तरफ लोग अन्न के बिना भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ अन्न बेकार जाएगा, सड़ेगा, इससे ज्यादा विडम्बना की स्थिति ओर क्या हो सकती है? आज यह स्थिति हमारे देश में है।

इसलिए अध्यक्ष महोदया जी, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप सीधे सरकार को निर्देश दीजिए कि किसानों के लिए बोरा और अनाज रखने के लिए गोदामों का इंतजाम करे। चाहे अन्न के बोरे रखने के लिए रेलवे के गोदाम मांगे जाएं या दूसरी जगह अन्न के बोरे रखने के लिए उपलब्ध कराई जाए, लेकिन किसान का पूरा का पूरा अन्न गोदामों में रखा जाए - यह हमारी मांग है। हमारे और भी साथी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे।

अध्यक्ष महोदया :

श्री आर.के.ि◌ंसह पटेल,

श्री नीरज शेखर,

श्री राधे मोहन सिंह एवं

श्री नामा नागेश्वर राव

को मुलायम सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (मुरैना): अध्यक्ष महोदया जी, पूरे देश में ही अन्न का उत्पादन बढ़ा है लेकिन विशेष रूप से पिछले 5-6 सालों में मध्य प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 49 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गयी थी और इस बार भी मध्य प्रदेश 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर केन्द्रीय पूल में देने का लक्ष्य तय कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार में किसानों को राहत देने के लिए अनेकों व्यवस्थाएं की गयी हैं। किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्हें एसएमएस करके मंडी में समय निर्धारित करके बुलाया जाता है, ई-पेमेंट की व्यवस्था की गयी है। किसानों का माल तुलता है और उसके खाते में पैसा जमा हो जाता है। लेकिन केन्द्र सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आज मध्य प्रदेश में बोरे की उपलब्धता नहीं है। किसान मंडी में खड़ा हुआ लाचार है, उद्वेलित है और ऊपर से मौसम भी बार-बार प्रतिकूल हो जाता है। कब पानी बरस जाएगा, कब किसान का अनाज खराब हो जाएगा, यह चिंता किसा की भी है, सरकार की भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने आंकलन किया और आंकलन करने के बाद।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य की बात के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) â€¦*

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदया, 269 हजार बोरों की गठानें खरीदने के लिए 4 करोड़ 78 लाख रुपया केंद्र सरकार को अग्रिम जमा करा दिया गया है। रुपया जमा कराने के बावजूद भी समय पर बोरियों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और केंद्रीय मंत्री जी से मिले। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस विषय को सदन में बार-बार उठाया और संबंधित मंत्रिगण से भी बातचीत की। सरकार ने आश्वासन दिया कि 30 अप्रैल तक आपको 61 हजार गठानें उपलब्ध करा देंगे, फिर कहा 5 मई तक उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आज तक 61 हजार बोरों की गठानों में से एक भी रैक मध्य प्रदेश में नहीं लगा है। इस कारण मध्य प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब हो रही है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी अनाज सड़ गया था और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देशित भी किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया। पूरे देश में आज फिर अनाज सड़ने की समस्या खड़ी होने वाली है। केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता और अग्रिम योजना न होने के कारण यह परिस्थिति खड़ी हो रही है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और श्री प्रणब मुखर्जी सदन के नेता सदन में बैठे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र बोरों की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि किसानों को मदद मिल सके और सरकार भी जिस संकट के दौर से गुजर रही है, उससे उबर सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भण्डारण की जो परेशानी है, वह भी केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता के कारण है। बड़ी मात्रा में वेयर हाउसेस बनाने का काम करना चाहिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि केंद्र सरकार अगर इस मामले में ध्यान न दे, तो महोदया आप कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष महोदया :

श्री राकेश सिंह,

श्री कीर्ति आजाद,

योगी आदित्यनाथ जी,

श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन,

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र,

श्री भूपेन्द्र सिंह,

श्री शिवराज भैया,

श्री के.डी. देशमुख,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्रीमती ज्योति धुर्वे,

श्री देवजी एम. पटेल,

श्री बालकिशन खांडेराव शुक्ला,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला,

श्री हरी मांझी,

डॉ. वीरेन्द्र कुमार,

श्री अशोक अर्गल और

श्री गणेश सिंह अपने आपको श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, यह मामला पिछले चार दिन से लगातार सदन में उठाया जा रहा है। एक बात तो साफ हो गई है कि जूट बैग का बड़ा संकट देश के सामने है। अभी भाई मुलायम सिंह जी और श्री तोमर ने इस सवाल को ज्यादा सदन के सामने रखा है। एक बात जरूर है कि जूट बैग फूड ग्रेंस के लिए रिजर्व था। सरकार के साथ कई वर्षों से प्लास्टिक बोरी वाले लाबी कर रहे हैं। हालत बहुत गंभीर है और मैं कहना चाहता हूं कि केवल यही एक मामला नहीं है। मामला यह है कि जो अतिरिक्त सरप्लस उत्पादन हुआ है, उसके लिए पिछले तीन वर्षों से हमने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई है। प्रणब बाबू मेरी जानकारी में स्टोरेज कैपेसिटी केवल 19 फीसदी है। बोरे तथा स्टोरेज कैपेसिटी दोनों अनिवार्य चीजें हैं। जब से दुनिया का बाजार डगमगाया है, अकेले हिंदुस्तान के किसान ने हर विपरीत परिस्थिति में, जब हर तरह से लागत ज्यादा हुई, इसके बावजूद भी उसने इस देश की आन, बान और शान को बनाए रखा। पेट की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस बारे में कई बार बहस हो चुकी है। गरीबी का मामला बहुत विकट है। विजुअल मीडिया सबसे अच्छा एक ही काम करता है कि अनाज के सर्वे को और भुखमरी को दिखाने का काम करता है। इससे देश का जो शासक वर्ग है, वह इसके जरिए ही जान पाते है कि देश की क्या हालत है।

प्रणब बाबू कल जवाब दे रहे थे, मुझे अफसोस है कि कुछ कारण से मैं यहां कल नहीं था। मैंने जो बात आपसे कही थी कि जो गोदाम हैं, ये जो वेअरहाउसेज हैं, गोदाम बनाने के लिए आपने सब्सिडी का 2009 में काम किया। क्या एक मीटिंग बुलाकर आप इसे नहीं देख सकते? नाबार्ड जो है, वह हमें बता रहा है कि इस बार सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी यह पहला कदम है जूट बैग और जो दूसरा कदम जिसका मुलायम सिंह जी ने जिक्र किया कि यह जो खाद्यान्न है, पिछली बार भी सड़ा है और आगे भी सड़ेगा। यह कहां रखा जाए और नहीं रखा जाए तो इसके डाइवर्सिफिकेशन का, किसी तरह से इसे काम में लाने के लिए हम यह कानून के दायरे में ही क्यों कर रहे हैं?

मैं एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री का मंत्री रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जमाने में इतना अनाज था और यहां यसवंत सिन्हा जी बैठे हुए हैं, यहां पर आडवाणी जी बैठे हुए हैं, मैंने 24 घंटे लगकर उस अनाज को डिसबर्स करने के कई रास्ते बनाये। क्या आप नहीं बना सकते? आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वह कहां पहुंचा? आपकी जीडीपी है, वह कहां पहुंची? कल जो आप सबसे अपील कर रहे थे, वह सिर्फ इस मामले में कर रहे थे कि बाजार कैसे टिक जाए? जो डीजल है, जब आप बजट रख रहे थे, तो मैंने पिछली बार आपसे कहा कि मॉल वालों को डीजल की सब्सिडी क्यों मिल रही है? होटल वालों को सब्सिडी क्यों मिल रही है? सैल टॉवर वालों को सब्सिडी आप क्यों दे रहे हैं? वे बाजार से कमा रहे हैं। आप इससे बेहतर किसान को क्यों नहीं राहत देते?

आप डीजल के दाम बढ़ाइए लेकिन आप इस वर्ग को देखिए कि जो हर तरह की दिक्कत में काम करता है। आप इस बात को देखिए कि जो अनाज सरप्लस में पैदा हुआ है, मैं प्रणब बाबू, खास तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में एक ही हिस्सा जो ईमानदार है और जो 80 फीसदी है, वह किसान है और उसके साथ मेहनत करने वाला मजदूर है जो पसीना बहाता है। वही आपकी लाज रखे हुए है। वही सारे देश की स्थिति में आपको कई खतरे से निकाले हुए है। हमारे जमाने में 3 वर्ष सूखा पड़ा। आज महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है। अनाज आपके पास काफी पड़ा हुआ है। आप डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता क्यों नहीं बनाते? मुझे बुलाइए। मुझे अनुभव भी है। यहां बहुत लोगों को किसान के बारे में अनुभव है। हम जमीन से आए हुए लोग हैं। हमसे बड़ी समझ प्लानिंग कमीशन के इन बैठे हुए लोगों में और अधिकारीगण में नहीं है।...(व्यवधान) हमें बुलाइए। हम आपको रास्ता बता देंगे लेकिन हिन्दुस्तान के अनाज की तबाही इस तरह से मत होने दीजिए। एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं और देश में अनाज सड़ रहा है, जैसे पिछली बार भी काफी अनाज सड़ा। कोई 19 करोड़ कहता है और कोई 70 करोड़ कहता है। वह भी सही सही पता नहीं चलता। आज सरप्लस कितना है, वह भी आप नहीं बताते हैं। कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई। हमारा कहना है कि यदि बम्पर क्रॉप हुई तो कितनी हुई? आपके पास कितना अनाज स्टोरेज में है? आपके पास सरप्लस कितना अनाज होगा और उसे कहां रखेंगे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोरी मिल जाएगी। गेहूं का इलाका 40 करोड़ किसानों का है। आज चावल के बाद सबसे बड़ा उत्पादन इस देश में गेहूं का है। हमने उसको गेहूं से अलग करने का कोई उपाय नहीं किया। जो किसान गेहूं में उत्पादन करता है और हम जो सब्सिडी देते हैं, वह सब्सिडी आप हर तरह के मामले में, जैसे यह जो आप डीजल पर सब्सिडी दे रहे हैं, सारे बड़े होटलों को दे रहे हैं, इनमें किस बात के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं? कारखानों को टिकाये रखने के लिए सब्सिडी देते हैं लेकिन जब किसान का सवाल आता है तो आप गंभीर ही नहीं हैं यानी हिलेरी क्लिंटन दुनिया भर में अपने बाजार के लिए जा रही हैं, चारों तरफ जा रही नं लेकिन आपके पास जो पूंजी है, हजारों वर्ष की जो विरासत है, जो किसान ने परम्परागत तरीके से अनाज पैदा किया है, उस अनाज को आप संभाल नहीं सकते। उस अनाज को आप देश में जो गरीब और भूखे

लोग हैं, उनको नहीं दे सकते। सारे लोग कहते हैं, लेकिन सरकार पर असर नहीं होता। कोर्ट कहती है तो कहा जाता है बेकार फालतू बात कह रहे हैं, कैसे बंटेगा? अरे, हमने बांटा है। हम आपको बताएंगे। आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 4-5 घंटे के लिए बुलाइए। हमको बोलने का मौका दीजिए। आप पार्टी के हिसाब से बुलवाते हैं। उसमें हमें कई बार समय ही नहीं मिलता है।...(व्यवधान) हम 40 वर्ष से यहां हैं। सरकार हमारी समझ और हमारे अनुभव को भी नहीं देखती है।

प्रणब बाबू, मैं आपके कमरे में दो बार गया। आप नहीं मिल पाए। हो सकता है आप काम में लगे हों। लेकिन उसमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जिससे देश आगे बढ़ रहा हो। लेकिन एक काम है जिसकी चिंता आपको है और वह है बजट का घाटा जो बढ़ता जा रहा है, आपका बाजार ठप्प हो गया और हर चीज ठप्प हो गई। अकेला यह किसान है, यह हिन्दुस्तान का अकेला मेहनतकश हिस्सा है जो महंगाई से त्रस्त है और हर तरह की दिक्कत के बावजूद भी आपके स्वाभिमान को बचाये हुए हैं। आप उसकी इतनी सी भी चिंता नहीं करेंगे कि उसने इतनी मेहनत से सारी चीजें की हैं और उनको आप ठीक से संभाल नहीं सकते। प्रणब बाबू, सब चीजों को छोड़कर आप किसान की चिंता करिए। हम सब चीजों पर आपको माफ कर सकते हैं। लेकिन आप इस किसान की चिंता कर लीजिए। आपकी सरकार को भी फायदा होगा। हमको लाभ हो या न हो, लेकिन हिन्दुस्तान को लाभ होगा क्योंकि हजारों वर्ष की हिन्दुस्तान की खेती है। सिंचाई का तरीका हमारा अलग है। लेकिन आप अनाज को सहेजने का काम भी ठीक से नहीं कर सकते। आप चारों तरफ घूमते हैं, आप रूस, अमरीका की तरफ देखते हैं। ये 700 साल, 500 साल से दुनिया को लूटे हुए लोग हैं, अब बाजार के जरिए लूटने के लिए निकले हैं और आपका बाजार थम नहीं रहा। आपके बस का नहीं है। इसके लिए आप एक मीटिंग बुलाइए। आप क्राइसिस ग्रुप बनाइए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। आप 5 घंटे के लिए इस पर चर्चा करवाइए। आप कोई रास्ता निकालिए कि इस अनाज का क्या होगा? इस मुद्दे को प्रायोरिटी पर लीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री शरद यादव जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ

श्री अर्जुन राय,

श्री जीतेन्द्र सिंह बुन्देला,

*m28 श्री हरि मांझी,

श्री दिनेशचंद्र यादव,

श्री महेश्वर हजारी,

श्री कौशलेन्द्र कुमार,

श्री भुदेव चौधरी,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री एम.बी.राजेश,

श्री कमलेश पासवान,

श्री उदासी शिवकुमार चनाबासप्पा,

श्री शिवराम गौडा,

श्री जी.एम.िसद्धश्वरा और

श्री पी.के.बीजु अपने आप को संबद्ध करते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, इस पर एक पूरे दिन बहस कराइए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अच्छा ठीक है।

â€¦(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, पिछले तीन दिन से लगातार इस सवाल को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और केवल बोरे की समस्या नहीं है, बल्कि और भी कई समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि हमारे देश में जो प्लास्टिक लॉबी है, उसका सरकार के ऊपर दबाव है कि जो जूट बैग है, जूट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लाखों मजदूर हैं और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में हैं।...(व्यवधान) जो कानून इस देश में है,...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦*

श्री बसुदेव आचार्य: जो 40 लाख किसान जूट उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं, इस जूट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए साजिश चल रही है। इसीलिए सरकार इससे पहले क्यों नहीं तैयार हुई?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruption)**

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार ने कोई शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म प्लानिंग नहीं की। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

श्री बसुदेव आचार्य: इस साल 253 मिलियन टन उत्पादन हुआ है।...(व्यवधान) और हमारे भंडारण की क्या स्थिति है?...(व्यवधान) शरद जी ने बताया कि 19 फीसदी है।...(व्यवधान) इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जूट बैग्स की उपलब्धि करवाए और वेअरहाउसिंग की व्यवस्था करवाए। अनाज सड़ रहा है।...(व्यवधान) हम मांग कर रहे हैं कि उस अनाज को गरीबों में बंटवाया जाए और जहां पर सूखा पड़ रहा है, वहां पर भी गरीबों में बांटा जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, आप शुरु करिए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज पंजाब राज्य के बारे में बोलना चाहती हूं। यह राज्य हिंदुस्तान के अमीरों और गरीबों का ही नहीं बल्कि सारे देश का पेट भरने में बहुत बड़ा योगदान देता है। चाहे गेहूं हो या चावल हो, आज 60 फीसदी से ज्यादा अन्न पंजाब पैदा करता है। पंजाब में हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरने के लिए एक नैचुरल रिसोर्स पानी ही है। पानी का लैवल इतना नीचे चला गया है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि 20 साल बाद पंजाब राजस्थान की तरह रेगिस्तान बन सकता है। यहां किसान खून पसीना बहाता है, यह राज्य अपना नैचुरल रिसोर्स खत्म कर रहा है और लगातार बम्पर क्रॉप दे रहा है। पंजाब के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है कि 120 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई है। यह अफसोस की बात है और आज स्टोरेज की बात पूरे देश में चल रही है। मैंने भी इस बात को कई बार संसद और समिति में उठाया है। आप पंजाब में जाकर देखिए कि आसमान तक अनाज से गोदाम भरे हुए हैं। गेहूं और चावल छः महीने बाद सड़ने लगता है, यह साल या डेढ़ साल से ज्यादा ओपन में स्टोर नहीं हो सकता है लेकिन यह चार-पांच साल सड़ता रहता है और हालत यह हो जाती है कि जानवर के खाने लायक भी नहीं रहता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यहां जितने सांसद बैठे हैं, एक तरफ सबको मालूम है कि हमारे क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी कितनी है और दूसरी तरफ मेरे संसदीय क्षेत्र में अनाज सड़ रहा है क्योंकि स्टोरेज की जगह नहीं है। सरकार क्यों नहीं इसे गरीबों मे बांटती है।

महोदया, आज पूरे देश में जूट बैग्स की कमी हो रही है। मौसम बदल रहा है, कभी मौसम बिगड़ जाता है और बरसात आ जाती है इससे तो 120 लाख मीट्रिक टन पड़ा हुआ अनाज खराब ही होगा। एक तरफ हम अनाज स्टोर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक्सेस बफर स्टॉक स्टोरेज करके स्टोरेज कम कर रहे हैं, अगर यही अनाज गरीबों में बांटा जाता तो यही अनाज को स्टोर करने की जगह बन जाती और दूसरी तरफ एक्सेस स्टोरेज करने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। मेरे द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में बताया गया था एक दिन का खर्च 27 करोड़ रुपए है। यह एक्सेस बफर स्टॉक को स्टोर करने के लिए होता है। इस तरह से एक साल में 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए हो जाता है। पैसे बर्बाद हो रहे हैं, अन्न बर्बाद हो रहा है, स्टोरेज कम है और गरीब भूख से मर रहा है और सरकार लगातार

सिस्टम और नियम को ठीक नहीं कर पा रही है।

मैं आपसे मांग करती हूं कि सिर्फ चर्चा ही नहीं इसका ठोस जवाब दिया जाना चाहिए कि कब तक ऐसे ही काम चलता रहेगा? क्योंकि नैचूरल रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, किसान का खून पसीना बहता जा रहा है और गरीब भूख से मरता जा रहा है।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Madam, under the PEG-2008 Scheme, PUNGRAIN, which is one of the State's own agencies and which was nominated by the Government of Punjab as the nodal agency, floated tenders for the creation of a total storage capacity of 51.25 lakh metric tones. The private entrepreneurs were offered Rs. 5 per quintal per month for bare space, apart from making a provision for escalation in preservation charges for proper maintenance of stocks.

I am given to understand that the private entrepreneurs have already constructed godowns. माननीय सदस्या ने जो बात कही है मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। गोदाम बन चुके हैं लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसी ने अभी तक गोदाम लेकर एफसीआई को हैंडओवर नहीं किए हैं। जो मसला चल रहा था।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Pratap Singh Bajwa says.

(Interruptions) â€¦

अध्यक्ष महोदया : ये क्या हो रहा है? आप खड़े क्यों हो गए हैं? बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात तो सुनिए। आपने अपनी बात कह दी है अब उनकी बात सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. You must learn to listen to others. Please sit down.

Now, Shri Pratap Singh Bajwa, please continue.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): I am given to understand that the private entrepreneurs have already constructed godowns with a storage capacity of 12.5 lakh metric tones and the rest of godowns with a storage capacity of 40 lakh metric tones would be ready in a few months' time. I am further informed that the State of Punjab need not spend even a single penny from its kitty.

It is the FCI that would be paying a sum of Rs. 1,800 crore to meet the costs of leasing bare space along with preservation charges. However, despite erecting the go-downs strictly as per the specifications approved by the FCI, the private entrepreneurs are waiting impatiently as to when the callous PUNGRAIN Authorities would handover these go-downs to the FCI for storage capacity. यही मैं कह रहा हूं कि कम से कम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। 24 घंटे यह गवर्नमैन्ट को...(व्यवधान) इन्हें खुद पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, ...(व्यवधान) ये सोये हुए हैं...(व्यवधान) पंजाब जल रहा है, किसानों का बुरा हाल है। हम स्टोरेज की कैपेबिलिटी बना चुके हैं, 52 लाख टन के हमारे गोदाम बन चुके है।

MADAM SPEAKER: Hon. Member, why are you standing up? Please sit down.

श्री प्रताप सिंह बाजवा: आप किसी की बात तो सुना करो।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझसे बात करिये। कृपया आप बैठिये।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA: Madam, the State agencies are unmindful of the growing damage and the mounting losses. They are selling the damaged paddy at Rs. 620 while they have spent Rs. 950 per quintal at the time of procurement, to the distilleries to be processed for branded alcohol, As a result of it, most of the distilleries have now shifted to grain-based alcohol from the conventional malt processing. ये सारा अनाज डिस्टलरियों को दे रहे हैं।...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप बैठिये।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: ...(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

(Interruptions) â€¦

श्री प्रताप सिंह बाजवा: ...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बाजवा जी, अब आप बैठिये। श्री दारा सिंह चौहान जी आप बोलिये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश के किसान असहाय स्थिति में हैं। मैं पूरे देश के किसानों को बधाई दूंगा, जिन्होंने इस देश में धान और चावल का एक रिकार्ड उत्पादन किया है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि जो पंजाब के मुकाबले अनाज उत्पादन में काफी आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में जो रिकार्ड गेहूं और धान पैदा हुआ है, उसके रखने को लेकर और बोरों को लेकर कई दिनों से चर्चा हो रही है। कल भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाया था कि आज पूरे देश में किसानों के द्वारा जो रिकार्ड उत्पादन किया गया है और स्टेट और सैंट्रल वेयरहाउसिंग के पास अनाज रखने की जो कैपेसिटी है, वह कुल साठ फीसदी है। मैंने कल भी सुझाव दिया था कि अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो मनरेगा में जो पैसा खर्च हो रहा है, आप उसका सर्वे कराकर अगर ब्लाक स्तर पर उस पैसे से यदि स्थायी गोदाम बन सकते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के किसान और हर गांव और ब्लाक के लोग उसमें स्टोरेज कर सकते हैं और अनाज को बचाया जा सकता है।

जहां तक बोरों का सवाल है, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। यह केवल किसी स्टेट का मामला नहीं है, आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार से मांग करता हूं कि बोरों की उपलब्धता तुंत कराई जाए, वरना बरसात के समय में सारे किसान तबाह हो सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, माननीय मुलायम सिंह जी अगर इस सवाल को...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री लालू प्रसाद: माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर आज इस सवाल को गंभीरता से नहीं उठाते तो शायद चर्चा करने का मौका भी नहीं मिलता।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): इस मामले में पहला हमारा नोटिस था।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री लालू प्रसाद: आप लोगों की बात मैंने नहीं सुनी। मैंने इनकी बात सुनी और उस चर्चा कर रहा हूं।...(व्यवधान)

मैडम सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस दिन से इस देश में वायदा मार्केट इंट्रोडयूस हुआ है, जिस दिन से वायदा मार्केट का जन्म हुआ है, उस दिन से किसानों के ऊपर आफ़त और तूफ़ान लागू हो गया। हर साल हम लोग इसी बात का रोना रो रहे हैं। सोना और चांदी की तरह गेंहू और चावल का दाम मुंबई में बैठक कर वायदा मार्केट वाले तय करते हैं। देश की जनता की थाली में दाल नहीं मिल रही है। हमारी दाल विदेश में चली गई है। जब मंत्री जी जवाब देंगे, तब बताएं कि क्या वायदा मार्केट एक साजिश नहीं है?

आज हमारा एफसीआई खरीद न कर के बोरा का बहाना कर रहा है। बोरा की रिक्यूज़िशन नवंबर में भारत सरकार को की जाती है। हर राज्य सरकार रिक्यूज़िशन करती है कि हमें इतने बैग चाहिए। स्टेटवाइज़, कौन से राज्य को नवंबर में आपने उपलब्ध कराया, किसने बोरा के लिए एप्लाई नहीं किया। गेहूं कहीं भी खुले आसमान में फेंका जा रहा है, चावल तो और भी नहीं लिया, गेहूं नहीं लिया, इससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। क्या यह साजिश नहीं है कि खुले आसमान के नीचे जब गेहूं फेंका जा रहा है और वायदा मार्केट किसानों से ले रहा है। फिर यही भाव बढ़ायेगा और आप विदेश से गेहूं लाने के लिए दौड़ेंगे। यह तो आपका ढोंग है, जो फूड गारंटी का आप वादा कर रहे हैं कि हम फूड गारंटी करेंगे, हम सिक्योरिटी कर देते हैं, हम गारंटी देते हैं कि हम किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। आपका यह कहना हास्यास्पद होगा। क्या यह बात सच नहीं है कि इन्फीरियर क्वालिटी बताकर गेहूं और चावल, दारू माफिया, जो दारू बनाने वाले लोग हैं, यह उनकी साजिश है, यह समूचा माल उनके पास चला जाएगा? जून महीने में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, जो सरकारी और सब लोगों को मान्य है, फिर आप गेहूं कहां से लाएंगे? आप यह बताइए कि किन राज्यों ने समय पर गेहूं के बोरे का रिविवजीशन किया और हर राज्य को कितना उपलब्ध कराया? वायदा मार्केट में बीच में बिचौलिया ले रहा है या नहीं, हमारे किसानों के गेहूं की लूट मची हुई है, कहीं भी उसके लाभ की बात नहीं हो रही है। जिस राज्य से हम लोग आते हैं, उस बिहार में भी कहीं कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में तो मुलायम सिंह यादव जी के पक्ष में अच्छा रिजल्ट भी दिया। ...(व्यवधान) इसलिए पहले से ही गेहूं के बारे में अच्छी व्यवस्था करें। ...(व्यवधान) सुनिये, यादव जी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आसन की ओर बोलिए।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, मैं इधर ही बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप आपनी बात समाप्त भी कीजिए।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, यह पूरी साजिश है। आप बोरे की उपलब्धता कराइए। बोरे उपलब्ध करा कर गेहूं व चावल को खरीदकर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कीजिए, इसके लिए जो भी गोदाम बनाना है, उन्हें बनाइए। जगह-जगह ब्लॉक किया जा रहा है। स्टोरेज के नाम पर क्या हो रहा है? गेहूं को नीचे बोरा या बैग में रखकर विमचिमी से ढका जा रहा है। विमचिमी मतलब प्लास्टिक का जो ऊपर से ढकने के लिए लगाया जाता है।

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद: मंत्री जी, आप इसका जवाब साफ-साफ दीजिए कि किन राज्यों ने बोरे के लिए समय पर रिक्विजीशन दिया और आपने कितना उन्हें उपलब्ध कराया? यह जवाब आना चाहिए।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you Madam Speaker for allowing me to speak on this important subject.

Madam, more and more State Governments have started procuring food grains from the farmers to ensure t;hat the farmers get the MSP because in the open market, the procurement price is very less. But my question is, whether procurement is for storage or for distribution? My view is that procurement should be for distribution. It means the distribution chain should be strengthened. For the APL family, the open market price of rice and wheat is more than Rs.25 and the MSP is Rs.11 or Rs.12 per kilogram.

I will suggest that the Food Corporation of India (FCI) itself can have a marketing division, open distribution chains and sell rice at the reasonable price, a little more than the Minimum Support Price (MSP) so that people will get rice at a cheaper price. We have been demanding for a universal Public Distribution System (PDS) in all States as it is happening in Tamil Nadu. We suggest that universal PDS should be there in every State. More and more States are going to procure more and more food grains. So, instead of thinking of storing these food grains, we must think to distribute it properly to the people so that the people will get rice at reasonable price. Thank you.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I am also associating with the matter raised by Shri T.K.S. Elangovan.

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की ओर से और हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी की ओर से इस देश के किसानों को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने गेहूं की इतनी पैदाइश की है, लेकिन आज गेहूं सड़ रहा है। मेरा यह कहना है कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि वह जो बोरा है, उसे इम्पोर्ट करना चाहते हैं, उसका बाहर के देश से आयात करना चाहते हैं। 80 परसेंट जो जूट की फैक्ट्रीज़ हैं, हेसियन बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं, वे पश्चिम बंगाल में हैं। पिछले 34 साल में वे सारी फैक्ट्रीज, जो सरकार तब सत्ता में थी, उन लोगों ने उन्हें बंद करके रखा है।...(व्यवधान) हमारी इंडस्ट्री को सहायता देनी चाहिए। पुनरूत्थान के लिए ...(व्यवधान) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें सहायता देनी चाहिए।...(व्यवधान) वेस्ट बंगाल में इससे काफी लोगों को काम मिल सकता है। ...(व्यवधान) इससे हम इसे आगे ले जा सकते हैं। (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गये हैं?

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हर समय ऐसा करना ठीक नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦*

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार : यह भी शर्म की बात है कि हमारे किसान गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन वह गेहूं सड़क पर सड़ रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये, शोर नहीं करिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार: मैं आपसे यह विनती करती हूं कि उस गेहूं को प्रोसेसिंग के माध्यम से क्यों न आटा बनाकर, क्योंकि 6 महीने तक रहने से वह सड़ जायेगा, तो मिनिस्ट्री के जरिये यह एक हमारी विनती है। उसे अभी प्रोक्योर करके आटा बनाकर पैकिंग करके रख दीजिये तो वह आटा 10 महीने तक भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।...(व्यवधान)

मेरी दूसरी मांग यह है कि मध्य प्रदेश...(व्यवधान) जब नवंबर, 2011 में बोरा का ऑर्डर दिया था, तब सिर्फ 9 लाख बोरा का ऑर्डर दिया था...(व्यवधान) अभी 12 लाख बोरा का ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, धन्यवाद।

श्री नामा नागेश्वर राव आप बोलिए।

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार: 12 लाख बोरा मांगने से नहीं मिलेगा।...(व्यवधान) उसके लिए कुछ न कुछ वक्त देना चाहिए...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में जो फैक्ट्रीज हैं, वहां से 80 परसेंट बोरा बनता है, जून महीने के पहले हफ्ते तक यह सारा बोरा पश्चिम बंगाल से मिलेगा। इसे इम्पोर्ट मत कीजिये, पश्चिम बंगाल को सहायता दीजिये ताकि 12 लाख बोरा जून के पहले हफ्ते में मिल जाये।

अध्यक्ष महोदया :

डॉ. रत्ना डे अपने आपको डॉ. काकोली घोष दस्तिदार जी के विषय के साथ सम्बद्ध करती हैं।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्मम): महोदया, पार्लियामेंट में चार दिन से बोरी के बारे में जिस तरह से बात चल रही है, हम सब जितने भी सांसद यहां बैठे हैं, we should feel shame. सुषमा जी ने इस बात को उठाया है, शरद यादव जी ने इस बात को उठाया है और आज मुलायम सिंह यादव जी ने यह बात उठायी है।

महोदय, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यह बोरी का विषय आज का नहीं है, पिछले साल आंध्र प्रदेश में बोरी नहीं मिली थीं, हमने किसानों के साथ रोड़ पर बैठकर धरना दिया था। पूरे देश में, आंध्र प्रदेश में चावल सड़ रहा था, चावल को स्कूलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में स्टोर किया। This is the fact. हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हम आपको उन्हें दिखा सकते हैं। इन लोगों की स्टोर करने की पोजीशन नहीं थी, पूरे का पूरा स्कूलों में स्टोर किया, मंदिरों में स्टोर किया। बोरी के बारे में पिछले साल भी यह प्रॉब्लम आयी थी और अभी भी यह प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट एकदम बेखबर है। समय-समय पर हम लोग जो प्रश्न लगाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इस साल का क्या प्रोडक्शन है, अगले साल का प्रोडक्शन क्या है, अपने रिप्लाई में आप लोग जो फिगर्स दे रहे हैं, इतनी फिगर्स के लिए आप लोग बोरी अरेंज नहीं कर पायेंगे, यह बहुत शर्मनाक है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

डॉ. संजीव गणेश नाईक।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदया, मैं एक मिनट और लूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, अब आप बैठ जाइये। संजीव गणेश नाईक जी आप खड़े हों और बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record, except what Dr. Sanjeev Ganesh Naik said.

(Interruptions) â€¦*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप बहुत लंबा लिखकर लाए हैं। You have made your point.

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦*

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार देश में सबसे ज्यादा रिकार्ड धान की उपज हुई है। ...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि इसके लिए केन्द्र सरकार को आदरणीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए कि इस बार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अनाज की पैदावार हुई है। ...(व्यवधान) किसी भी प्रकार की फसल हो - धान हो या गेहूँ हो या गन्ना हो, हर चीज़ की पैदावार ज्यादा हुई है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस साल किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा बढ़ाकर देने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा किसान दुख दर्द में जाएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? Show some respect for time. Please sit down.

डॉ. संजीव गणेश नाईक: मैं अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय मंत्री जी से मांग करूँगा कि इस पर सरकार ध्यान दे। जैसे इस सदन के सभी अनुभवी सदस्यों ने कहा कि पिछले तीन साल से हम देख रहे हैं कि अनाज का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। हमारे किसान सोच रहे हैं कि हर साल हमारी आबादी बढ़ रही है तो धान की आवश्यकता बढ़ेगी। इसके बारे में सरकार को भी बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से मांग करूंगा कि सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने पर ध्यान दे।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, we are very proud of Indian farmers. As other hon. Members said, agricultural production has increased this year.

Madam, in Tamil Nadu, our hon. Chief Minister has taken all steps to protect the interests of the farmers. She has given a lot of incentives to the farmers. That is why, agricultural production has increased in Tamil Nadu. At the same time, we are requesting the Central Government to come forward to help the farmers.

As all other hon. Members mentioned, after procurement, we have to store the food grains. For that, we need proper godowns. That is what we are facing shortage of. Then, other hon. Members also mentioned about the shortage of gunny bags. Some other hon. Members also spoke about distribution. Then, we should also see how to distribute to the consumers whatever is procured. In that respect, Tamil Nadu is a pioneer now. We are giving free rice to all the family cardholders. We are still following that. That has to be followed because after production by farmers, it has to reach the consumers because the people of this country are very poor. For that, we require incentives from the Central Government. Our Chief Minister had also written a letter to the Central Government regarding Thane Cyclone. While the said cyclone had hit the State of Tamil Nadu last year, the Central Government has not yet given the money. The State Government solely went to the rescue of the farmers and started so many programmes. Therefore, I would request the Central Government to come forward to release urgently the money the Chief Minister has asked for in her letter written to the Central Government.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, during the last four days including today, the issue that has been actually troubling all of us is relating to jute bags. We should also recollect the amount of neglect the jute crop has faced during the last four decades. Today, if the jute factories of West Bengal are suffering, it is because, what Shri Basu Deb Acharia has rightly mentioned, our attention has been shifted towards plastic commodities.

I also recollect that two or three days back, the Leader of this House, hon. Finance Minister, had very categorically mentioned that he is requesting the Left and also the Trinamool Congress to impress upon the jute factories to increase production. I would also request the Government to impress upon the Bangladesh Government where jute production is very high in quantity and also of very high quality. We can import jute bags immediately to tide over the situation.

At the same time, I would also make a request to the Government. Invariably in every State, wheat and paddy production has increased manifold. Even in a State like Odisha, which was and is a surplus paddy growing State, the purchase of paddy is more than 30 lakh tonnes, but the storage capacity of the FCI there is hardly four lakh tonnes and that of the State Government is another five lakh tonnes to six lakh tonnes. Further, as it is called, with Private Entrepreneurship Guarantee Scheme, another three lakh metric tonnes capacity building or storage is now being developed.

Odisha has been entrusted with a specific procurement of rice that is called, custom-milled rice because we need that type of rice for the Eastern coast, which is actually being used by the people there. For this also, we have asked the Central Government to provide us with support so that respective State Governments can also have godowns for custom-milled rice. I am saying this because the problem today is lifting of food grains immediately, that is, once it is procured. But today, the concern is how to store it, and for storage, we need best quality gunny bags or jute bags. I think that we would have to look forward to it, and I think that the Central Government has to come up in a very big way.

MADAM SPEAKER: Thank you so much.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, please allow me for one minute. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I think that this subject is over.

Yes, the Leader of the House.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I would just like to share a few points because the other day I had responded to Shri Sharad Yadav.

This morning, Shri Mulayam Singh and others raised this issue. The problem, which arose, as Shri Lalu has pointed out, that this is the practice that every year in the month of November there is a meeting of the State Governments and the Food Ministry; their indents are placed; according to those indents requirement is placed it to DGS&D; and DGS&D supplies it from the jute mills and through their own procurement and supply arrangements.

This time, two distortions have taken place so far as Punjab and Haryana, the two major producing States, are concerned. I have the figures with me. Substantially, their indents have been fulfilled. Two types of problems arose substantially in Madhya Pradesh (MP) and also in Uttar Pradesh (UP).One is that the level of expectation of procurement by the State administration at that point of time was less, and the actual procurement was much more. For instance, in November, the MP Government projected that their procurement would be about 65 lakh tonnes, but their actual procurement has been more than 85 lakh tonnes. They had to procure it when the farmers produce it and bring it to the market. No State agency can refuse to buy it. So, the required quantity of jute bags, in terms of bales, has also increased substantially. They have made a revised programme and as per that revised programme, the supplies are being made.

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रणब बाबू से कहना चाहता हूं कि इस समस्या का निदान सम्पूर्ण तरीके से करना होगा। अनाज सरप्लस पैदा हो रहा है, लेकिन उसका रखरखाव न होने के कारण अनाज का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस मामले में पेडी और व्हीट का सरप्लस उत्पादन हुआ है। यह 40 करोड़ लोगों का मामला है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जूट बैग तो पहला कदम है, Jute bag is the first step. लेकिन इसके बाद स्टोरेज आता है, जिसके लिए आपने वर्ष 2009 में सब्सिडी दी थी।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I am coming to that point.

श्री शरद यादव: इसलिए मैं सरप्लस अनाज के बारे में आपकी चिंता चाहता हूं, सरकार की चिंता चाहता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : आपने जो सवाल उठाया था, यही सवाल दूसरे मैम्बर्स ने भी उठाया था। लालू जी ने भी यह सवाल उठाया कि किस स्टेट ने नवम्बर महीने में कितना इनडेंट दिया था? इसलिए उनको भी तो इस बारे में जवाब देना चाहिए! उन्होंने स्पेशली एक सवाल पूछा था।

13.00 hrs

As I have said, for construction of the godowns, banks will provide concessional rate of interest. We will also provide support even from the Viability Gap Fund. We have also made arrangements in this Budget that will allow you to have External Commercial Borrowings because the interest rate is lower there, of course with a ceiling, because I cannot increase the short term borrowings substantially. So, all these steps are taken but that does not mean that tomorrow the godown will come. If I announce the programme today, godowns will not come tomorrow. It will take some time. The problems which you posed, as I understood is that any moment rains may come and those grains are lying in the open area. Now, the main problem is how to protect it, how to make contingency arrangement for the immediate requirement. That is why, we sent our officers to Kolkata. Current production of the jute bags is 2 lakh and 50 thousand per month. We have asked them to produce more and they are actually producing now 25 thousand additional bags, and the production will become 2 lakh and 75 thousand bags. I hope there will be no strike in between and will not suspend the production. Sometimes, they put pressure as this is the procurement season. So, sometimes some trade union leaders also indulge in this type of activities. I am assured that this year there will be no strike. ...(*Interruptions*) No, I myself had to deal with it. Then, your Minister was there. I had called him and told them that do not put pressure at the time of procurement season. In that case, I would be compelled to allow the plastic bags. Then, it was stopped.

Therefore, I have my own experiences. I am not speaking in vaccum. I requested them and fortunately, I also had a discussion with West Bengal Industries Minister, Mr. Partho Chatterjee. I requested him to ensure that the production continue uninterruptedly to solve the immediate problem of availability of the jute bags. I have also suggested in the morning after Mulayam Singh Ji raised the issue, I requested the Food Minister to come to my room. Shri Rewati Raman Ji was also there. For the solution, UP Government has made some suggestions. We are complying with that and in the next 5 to 6 days, those problems will be resolved. But that is temporary. Even if I want to import and, today I decide to import, tomorrow, the imported goods do not come. It takes time. All these issues are to be addressed but I accept one suggestion of Shri Sharad Yadav Ji that this is a problem for which we require a medium to long term solution. How can we do this? I

am ready to sit with the Leaders of the various political parties, get their inputs and to work out a mechanism. Every year, we are not confronted with this problem. Shortly, I would also like to add to resolve the immediate problem.

There is a provision, I do not want to resort to that provision. But if there is any requirement, then we will resort to it. Our target is to protect the crop, so that it is not destroyed and then, to go to the biodegradable packaging material. That is second thing. Therefore, there is a provision in the Jute Act itself that if adequate quantum of jute bag is not available, then substitute plastic bags for a temporary period could be used. We are exploring all those possibilities though I myself do not want plastic bags to be used for storing the grains.

You will recollect, in 1985 when Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, in order to protect the jute industry, he ensured that three commodities namely, cement, sugar and food grains were packed in biodegradable bags. Now, cement has gone out of jute packaging. Sugar and food grains are still there. We are ensuring that it is available. Three ministries are there. Only Food Ministry cannot do this. Their job is to coordinate. I am going to have a meeting with them. I will see that as early as possible, these problems are resolved. Thank you.

SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): What about godowns? ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Gopinath Munde says.

(Interruptions) â€¦*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have already informed the House that the Rural Development Ministry has been asked to explore the possibilities of food for work through the MGNERGA and other programmes as to what can be done and how it should be tied up. But that cannot happen immediately because the State Governments will have to agree to this. They will have to be involved. They are the implementing agencies. So, it is not that today I say it and tomorrow it would start. But the Ministry has been sensitized and they are working on it.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: That is enough.

MADAM SPEAKER: Shri Gopinath Munde.